खजुराहो-सतना और रीवा-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दिए जाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी उक्त रेल लाइनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो और रीवा-सीधि-सिंगरौली रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण-कार्य शुरू कर दिया गया है । आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सेंट्रल जोन काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में इस लाइन की सिफारिश की है ।

Degradation of the global environment

*214. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the developed countries which are primarily responsible for the degradation of the global environment, have committed the date of putting their contribution of 0.7 percent of GNP for Official Development Assistance; if so, what are the details thereof;

(b) what is the quantum in terms of dollar, the 0.7 per cent of GNP comes to; whether this is a recurring amount or lump sum; and

(c) the financial assistance required to meet 100 percent the problem of degradation of global environment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) At the United Nations Conference on Environment and Development held at Rio de Janeiro in June, 1992, the developed countries re-affirmed their commitment to reach the accepted United Nations target of 0.7 per cent of Gross National Product (GNP) for Official Development Assistance and, to the extent that they have not achieved the target, agreed to augment their aid programmes in order to reach the target as soon as possible.

(b) On the basis of current Gross National Product (GNP) of developed countries, the Official development Assistance (ODA) to Gross National Product (GNP) ratio of 0.7 per cent is estimated to be approximately US $ 120 billion per annum.

(c) The Secretariat of the United Nations Conference on Environment and Development have estimated that the average annual cost for implementing environment protection activities in developing countries ,as envisaged in Agenda 21, would be ovtr US $ 600 billion for the period from 1993 to 2000 A.D.

Selling of Indo-Pak border

*215. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that, following eruption of trouble in Sindh the Government of Pakistan has decided to seal the border with India;

(b) if so, what are the steps taken by Government to seal the entire Indo-Pak border in view of Pak infiltration in Punjab and Jammu and Kashmir; and

(c) whether Government have fixed any target date for the completion of sealing the entire Indo-Pak border?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) The Government have seen such reports since the launching of Operation Blue Fox in Sind by Pakistan Army.

(b) and (c) Border fencing and flood lighting at most of the sensitive and vulnerable stretches has been completed on

the Indo-Pak border in Punjab and Rajasthan and for the remaining areas in these States, similar action is in progress. Adequate measures have also been taken to further strengthen the border in Jammu & Kashmir. Steps are also being initiated to provide the BSF with the necessary equipment, and the wherewithal to effectively check unauthorised movement across the border.

उड़ीसा के अस्पतालों में रिक्त पद

*216. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में चलाए जा रहे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन अस्पतालों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और वे कब से रिक्त हैं ; और

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक भर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में केंद्रीय सरकार के अधीन चार (4) अस्पताल हैं । इन अस्पतालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेल मंत्रालय

1. रेलवे अस्पताल, खुर्दा रोड ।
2. रेलवे अस्पताल, बांडामूंडा ।

श्रम मंत्रालय

3. केंद्रीय अस्पताल, जोडा ।

गृह मंत्रालय

4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अस्पताल

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में कुछ स्वायत्तशासी अस्पताल हैं तथा ऐसे अस्पताल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए है:—

स्वायत्तशासी अस्पताल

1. ई.एस.आई., अस्पताल, ढोडुवार ।
2. ई.एस.आई, अस्पताल, ब्रजराज ।
3. पारादीप पत्तन अस्पताल ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्पताल

1. आयरन माइन्स हास्पिटल, बरसुआन ।
2. बी.एस.एल. कंपनी हॉस्पिटल, बीरमित्रपुर ।
3. नेलको हॉस्पिटल, दमनजोडी ।
4. नेलको हास्पिटल, अंगोल ।

चूंकि उपर्युक्त कोई भी अस्पताल इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत नहीं है, इसलिए इन अस्पतालों में रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, जहां तक खुर्दा रोड स्थित रेलवे अस्पताल का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि उस अस्पताल में पदधारी के अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने के कारण एक रिक्ति थी ।

दिल्ली में मिलावट वाले पेट्रोल की बिक्री

*217 **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के कुछ पैट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल मिला हुआ पैट्रोल बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार की इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली के पैट्रोल पम्प